

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

भाग 1

2. "उचित पोषण मानव विकास की आधारशिला है"

"पहला सुख, निरोगी काया"

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होता है कि मानव जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए रोगमुक्त शरीर का होना अत्यन्त आवश्यक है। रोगमुक्त शरीर का आशय मानव के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य का किसी भी विकार से मुक्त होना है तथा इन सबकी प्राप्ति के लिए जो चीज सर्वाधिक आवश्यक है, वह है पोषण का उचित मात्रा में होना।

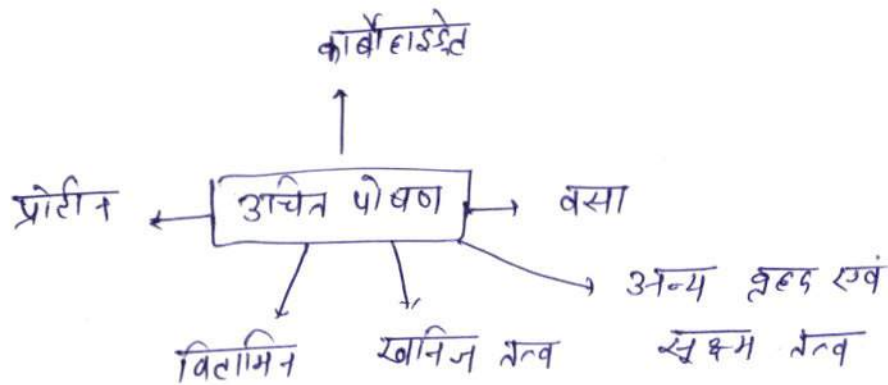
उचित पोषण मानव शरीर की अनेक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुलित विकास में सहयोग प्रदान करता है। परन्तु वर्तमान में भारत में उचित पोषण परिदृश्य की दयनीय स्थिति है। विश्व के सर्वाधिक

संख्या में कुपोषित बच्चे भारत में रहते हैं।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का 100 वां
स्थान भोजन एवं पोषण परिदृश्य के सकारात्मक
चित्र को प्रस्तुत करता है। इसी के साथ-साथ
भारत में खराब पोषण के कारण संतुलित मानव
विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसके
कारण भारत की बहुमूल्य मानव पूंजी के
अप्रभावी एवं अनुत्पादक होने की समस्या
का सामना किया जा रहा है।

इसलिए संतुलित मानव विकास को
~~समर्थन~~ सुनिश्चित करने के लिए उचित पोषण
का आशय, इसके संघटक, इसके लाभ एवं हानियों,
सरकारी एवं निजी प्रयासों, प्रयासों में व्याप्त कमियों
व्या उपमुक्त समाधानों को पर विचार करने
की आवश्यकता है ताकि भारत में पोषण
परिदृश्य में सकारात्मक सुधार लाकर सामाजिक,

आर्थिक तथा मानव विकास को सुनिश्चित किया जा सके ।

उचित पोषण का सामान्य तात्पर्य शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा का समय पर पर्याप्त होना है।



उचित पोषण के संघटकों में वृहद पोषक तत्वों तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ-साथ कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन को शामिल किया जाता है। इसी के साथ भोजन में इनके उचित अनुपात का होना भी आवश्यक होता है, जो मनुष्य की आयु, लिंग, कार्यशैली इत्यादि के अनुसार अलग-अलग होता है।

उचित पोषण में केवल पेट भरने को ही शामिल नहीं किया जाता, अपितु मानव शरीर के सभी अंगों की उचित वियाशीलता के लिए सभी आवश्यक पदार्थों के ग्रहण करने को भी शामिल किया जाता है। उचित पोषण के कारण मानव शरीर का बहुआयामी विकास संभव होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास सम्मिलित हैं।

उचित पोषण के कारण मानव शरीर को अनेक बीमारियों जैसे ठिगनापन, अल्पवजन, रूनीमिया, व वाशियोरकोर, रतौंधी, जलगण्ड इत्यादि से बचाने में सहायता मिलती है। इससे मानव का बीमारियों पर होने वाले अनावश्यक खर्च से भुक्ति मिलती है। क्योंकि भारत में प्रत्येक वर्ष लाखों लोग इसके कारण गरीबी के दृबचक्र में फंस जाते हैं।

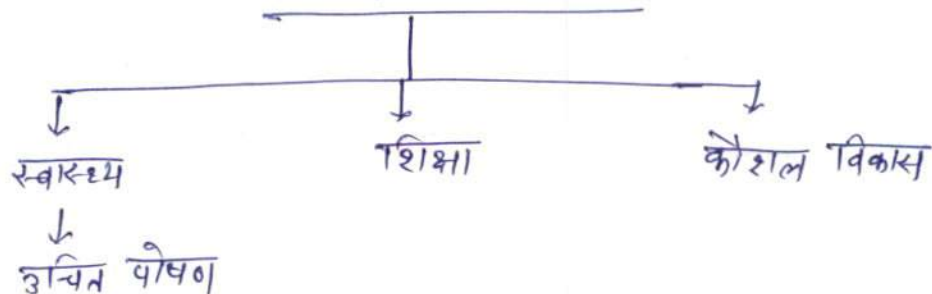
इसी के साथ लॉसेट रिपोर्ट की 'स्ट्रेट डिजिज बर्डन रिपोर्ट' में भी भारत की स्थिति को सुधारने में सहायता मिल सकती है। उचित पोषण उम्र के अनुसार स्वस्थता से धुनिश्चित

करता है, जिससे व्यक्ति कुशल मानव पूँजी के निर्माण में अपना योगदान दे पाता है। इससे भारत के जनसांख्यिकीय लाभों के सकारात्मक प्रयोग में सहायता मिलेगी और आगे चलकर यह भारत के आर्थिक विकास को समृद्ध एवं तीव्र करने में सहायक होगा। आर्थिक विकास होने से सामाजिक निवेश में यह सहि से मानव विकास और अधिक सुदृढ़ होगा।

मानसिक स्वास्थ्य के सही होने की स्थिति में भारत में एक विचारशील जनसंख्या का निर्माण होगा तथा आत्महत्या जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी, इसी के साथ उचित पोषण के कारण वैश्विक भुखमरी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, WHO की पोषण रिपोर्ट इत्यादि में भारत की स्थिति में सुधार के फलस्वरूप भारत की वैश्विक छवि में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा, जिससे भारत में निवेश करने की संभावना है तथा आगे चलकर यह रोजगार सृजन, आर्थिक विकास तथा अन्ततः मानव विकास की ओर एक अशक्य कदम होगा।

उचित पोषण के कारण सतत विकास लक्ष्यों (2030) को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी तथा इसके फलस्वरूप भारत आर्थिक विकास को तीव्र कर वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा।

मानव पूंजी के 3 स्तंभ



इसलिए कहा जा सकता है कि उचित पोषण न सिर्फ मानव जीवन के व्यापक स्तर को सुनिश्चित करता है, अपितु यह सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में अपने योगदान के माध्यम से वृहद् मानव विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। उपर्युक्त रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि देश में कुशल मानव पूंजी निर्माण के लिए उचित पोषण एक अनिवार्य शर्त है।

जब मानव को आवश्यकतानुसार उचित पोषण की प्राप्ति नहीं हो पाती तो उस स्थिति

को कुपोषण की स्थिति कहा जाता है। भारत में
वर्तमान में दो प्रकार के कुपोषण का सामना
किया जा रहा है। ये हैं-

- (1) अल्पपोषण
- (2) अतिपोषण

अल्पपोषण के अंतर्गत आवश्यक पदार्थों
से कम मात्रा में पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, जिसके
कारण 'स्ट्रॉकिंग', 'वेस्टिंग', एनीमिया, विटामिन की कमी
से होने वाले रोग इत्यादि का सामना करना पड़ता
है। वहीं अतिपोषण में आवश्यक पदार्थों की मात्रा
से अधिक मात्रा में पोषण पदार्थ ग्रहण किये जाते
हैं जिसके कारण मीठापा, मधुमेह, हृदय रोग इत्यादि
का सामना करना पड़ता है।

अतः उचित पोषण की प्राप्ति के लिए
अल्पपोषण एवं अतिपोषण दोनों समस्याओं पर नियंत्रण
अनिवार्य है सभी एक संतुलित मानव विकास की
ओर अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। उचित
पोषण की सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक

स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं -

- (1) इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक का प्रकाशन।
- (2) 'WHO' द्वारा पोषण रणनीति की घोषणा।
- (3) संयुक्त राष्ट्र के नवाधान में समग्र विकास लक्ष्यों की घोषणा।
- (4) विश्व बैंक एवं WHO द्वारा भारत में अनेक पोषण कार्यक्रमों में सहयोग।

राष्ट्रीय प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रयास

निम्नलिखित हैं -

- (1) हाल ही में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसमें 0 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय

व्यापक पैयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की सहभागिता है। इसके अंतर्गत स्ट्रिंगिंग, वेस्टिंग व अल्पपोषण को प्रतिवर्ष 2% कम करने तथा रूनीमिया को प्रतिवर्ष 3% कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मिल स्कीम के तहत बच्चों में कुपोषण की स्थिति से लड़ने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इस भोजन के लिए उचित पोषण भंडारक निर्धारित किए जाते हैं।

(3) संयोजित बाल विकास सेवा (ICDS) के अंतर्गत बच्चों एवं किशोर तथा गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है तथा उन्हें समय-समय पर पूरक पोषण उपलब्ध करवाया जाता है।

(4) राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत साप्ताहिक फोलिक एसिड एवं आयरन की

सौलियों का वितरण किया जाता है ताकि अनिमिया जैसी समस्या से निजात पाया जा सके।

(5) सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से गरीबों को अनाज, दालें, नमक, तेल इत्यादि उचित कीमत पर प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

(6) सरकार द्वारा भोजन में पोषक तत्वों के समीक्षण के लिए 'फूड फोर्टिफिकेशन' पर कल दिया जा रहा है।

(7) इसी के साथ दालों के उत्पादन में विस्तार तथा 2018 को मौटा अनाज वर्ष घोषित करना भी एक सराहनीय कदम है।

इसके अलावा भी सरकार अनेक निजी व सिविल संस्थाओं के साथ मिलकर

अनेक कार्यक्रमों का संचालन कर रही है ताकि उचित पोषण भी प्राप्त किया जा सके। परन्तु इन प्रयासों के बावजूद भी भारत में उचित पोषण परिदृश्य का नकारात्मक दृशा में होना चिन्ताजनक है। इसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक कारणों को उत्तरदायी ठहराया जाता है।

भारत में अनेक मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं में समन्वय एवं अभिसरण (Convergence) का अभाव है। इसी के साथ सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन भी निम्न स्तर पर विद्यमान है। उचित प्रौद्योगिकी के अभाव एवं सीमित प्रशासनिक प्रयासों के कारण इन कार्यक्रमों की जनता तक अपर्याप्त पहुंच है।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों में विभिन्नता है तथा एक उचित राष्ट्रीय पोषण रणनीति का अभाव है जिसमें एक स्पष्ट रोजमैरा के साथ आपनीय एवं प्राप्त करने योग्य स्तर

लक्ष्यों का अभाव है। साथ ही साथ जनता के मध्य उचित पोषण के अर्थ तथा इसके प्रभावों के बारे में व्यापक जागरूकता का अभाव है। सरकार सर्वाधिक सुबेद्य वर्गों जैसे, महिलाओं, बच्चों, किशोरों इत्यादि पर अलग से विशेष नीति बनाने में असफल प्रतीत होती है।

जनता एवं समाज द्वारा केवल भोजन प्राप्ति को ही सब कुछ माना जाता है। अतः लोगों की इस अभिवृत्ति में बदलाव करना जरूरी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि, उचित पोषण स्थिति प्राप्त करने के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनका बहुआयामी प्रयासों के माध्यम से समाधान अत्यन्त आवश्यक है।

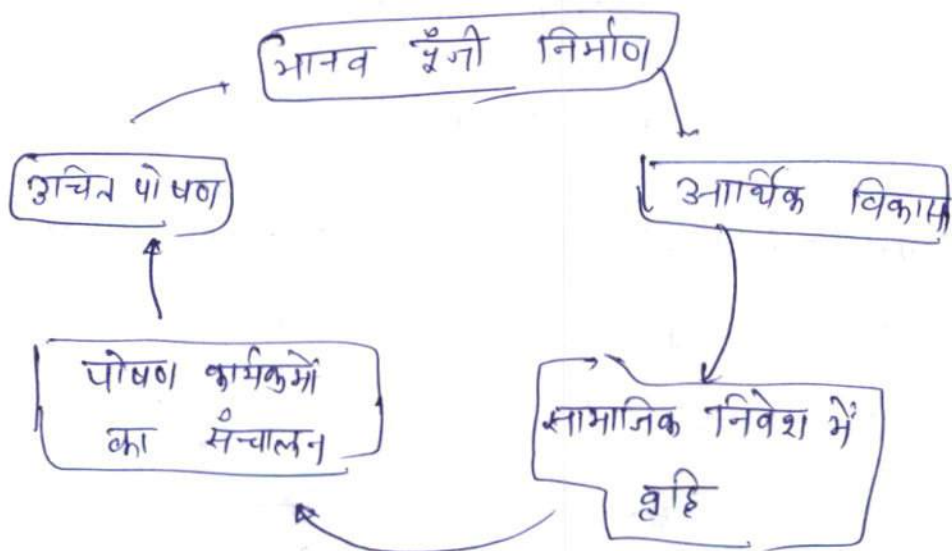
सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट लक्ष्यों एवं रोडमैप के साथ पोषण नीति का निर्माण एवं उसका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। सभी केन्द्रीय एवं राज्य मंत्रालयों की सभी योजनाओं

के अद्य लक्ष्योपयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। अन्तिम धारित तब योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग जिसमें आचार स्थापन, बैंक खाता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण इत्यादि आवश्यक हैं।

इसी के साथ सरकार को योजनाओं के कार्यान्वयन में उचित प्रशासनिक सक्रियता दिखाने हुए सिविल समाज का सशक्त सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए ताकि योजनाओं के विस्तार एवं पहुंच को प्रभावी बनाया जा सके।

इस सभी प्रयासों के अलावा जनता में पोषण संबंधी जागरूकता का प्रसार करना चाहिए जिसमें मीडिया का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं सब प्रयासों के फलस्वरूप भारत में एक ~~बेहतर~~ सकारात्मक पोषण परिदृश्य का निर्माण होगा, जिससे धार्मिक मानव विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय मानव विकास

परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन आने की पर्याप्त संभावना है। सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के कारण भारत की वैश्विक छवि में सुधार होगा तथा इसके साथ भारत में एक स्वस्थ एवं कुशल मानव पूँजी का सृजन संभव होगा जो दीर्घकाल में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ मानव विकास को भी सुनिश्चित करेगा। इसे निम्नलिखित चक्र से प्रदर्शित किया जा सकता है।



और अन्ततः हमें इस श्लोक

को साकार करने में सहामता मिलेगी -

१ सर्वेः भवन्तुः दुःखिनः, सर्वे सन्तुः निराभयाः ।
सर्वेः अज्ञानिः पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखमाग्भवेत् ॥

इसलिए कहा जा सकता है कि उच्च
मानव पौष्टि मानव विकास की आधारशिला है।

भाग 2

गरीबी और जलवायु परिवर्तन से लड़ाई: विकासशील
देशों के लिए चुनौती

हाल ही में भारत के लक्ष्य द्वीप समूह में स्थित पराली - I द्वीप डूब गया तथा साथ ही प्रशान्त महासागर में भी अनेक द्वीपों पर खतरा मण्डरा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अन्तरसंस्कारी पैनल ने 2007 में अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि 300 तक पृथ्वी के तापमान में 2°C से अधिक की वृद्धि होने के कारण मानव समुदाय को विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ेगा विशेषकर विकासशील देशों को, क्योंकि इन्हीं देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य गरीब नागरिक निवास करते हैं।

इसी के साथ जलवायु परिवर्तन के

कारण धुखे एवं वाट की बारंबारता के फलस्वरूप भी विकासशील देशों की ज्यादा कठिनाई एवं विनाश का सामना करना पड़ रहा है।

वस्तुतः गरीबी एवं जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को विद्वानों द्वारा एक दुष्चक्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये दोनों काफी निकट संबंध होते हैं तथा एक-दूसरे के कारण एवं प्रभाव होते हैं।

गरीबी के कारण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। गांवों में गरीब लोग ठोस जीवाश्म ईंधन का भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे हानिकारक हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। इसी के साथ किसानों के पास उचित तकनीक का अभाव होता है, ताकि वे अपने फसल अवशिष्ट का निपटारा कर सकें। इसीलिए वे फसल अवशिष्ट को जलाकर जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं।

गरीब देशों में विद्युत के अभाव के कारण स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश नहीं हो पाता। जिलेके फलस्वरूप उद्योगों एवं वाहनों में निम्न प्रौद्योगिकी तथा जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है,

जनजातीय समुदाय अपने आवास, भोजन एवं आजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं जिसके कारण अंधाधुंध वनों के कटाव व क्षम क्षैत्री के कारण वनाकरण में कमी आती है।

इसी के साथ गरीबी के कारण प्राकृतिक संसाधनों का भी निर्मम दोहन किया जाता है। परन्तु जलवायु परिवर्तन भी इस गरीबी को बढ़ाने में अपना योगदान देता है, क्योंकि गरीब समुदाय के पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपायमत्त संसाधन नहीं होते हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़

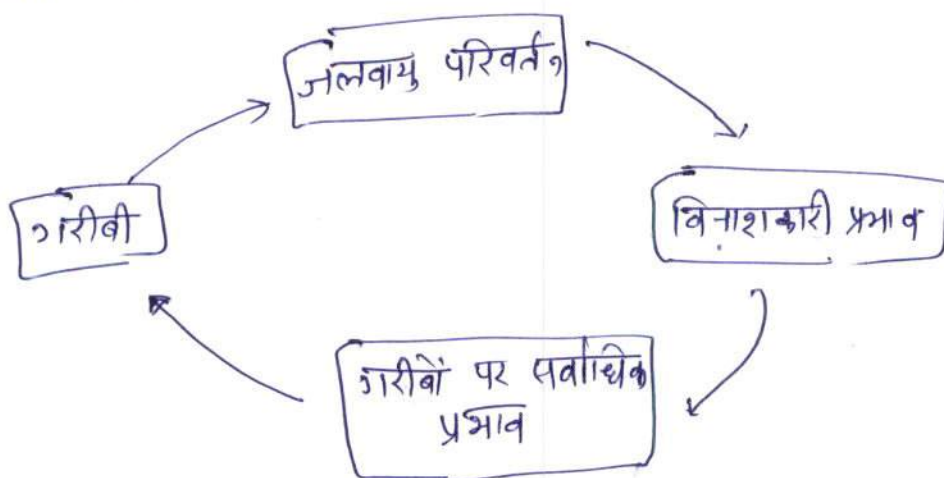
की सीढ़ी में वृद्धि के फलस्वरूप किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। सूखे के कारण फसल उत्पादन नष्ट होने के कारण किसानों की आय में कमी आती है, जिससे वे गरीबी के दुरुचक्र में फंस जाते हैं।

इसी के साथ जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक बीमारियों तथा महाभारियों के प्रसार में निरन्तर वृद्धि हो रही है जो गरीब लोगों को सर्वाधिक प्रभावित करती है। इसी के साथ बीमारियों पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य व्यय के कारण अनेक लोग गरीबी के दुरुचक्र में फंसते जा रहे हैं।

दरीफ समुद्रों के जलमग्न होने तथा जलीय जैविक संसाधनों में हास के कारण मछुआरों के जीवन के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाते हैं। वनों के विनाश के कारण जनजातीय समुदाय के जीवन के समक्ष संकट उत्पन्न होते जा रहे हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन एवं गरीबी के मध्य एक घनिष्ठ संबंध है जो विकासशील देशों में व्यापक रूप में मौजूद है।

जिस वर्तमान समय में यह दुष्चक्र इन देशों के आर्थिक एवं भाव विकास को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर रहा है।



निष्ठा: गरीबी एवं जलवायु परिवर्तन का दुष्चक्र

वर्तमान समय में विकासशील देशों के समक्ष ये दोनों चुनौतियां विकराल रूप धारण किए हुए हैं। इन समस्याओं के पीछे विशेषतः

द्वारा अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

विकासशीलों देशों को अपनी जनसंख्या के कल्याण के लिए आर्थिक विकास को

प्राथमिकता देनी पड़ती है तथा आधुनिक तकनीक के अभाव के कारण तथा विकसित देशों के पर्याप्त सहयोग के अभाव के कारण उनको पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर उत्पादन करना पड़ता है जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है।

पेरिस सम्मेलन तथा म्योरो प्रोटोकॉल जैसे वैश्विक प्रयासों में विकसित देशों की रुचि एवं सहयोग के अभाव के कारण जलवायु परिवर्तन का ज्यादा बुरा विकासशील देशों पर पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण विकासशील देशों को अनेक समस्याओं व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें बाढ़ व सूखे की बारंबारता में वृद्धि, फसल उत्पादन में गिरावट, अनेक बीमारियों के प्रसार के कारण स्वास्थ्य क्षय में वृद्धि, भूस्खलन का तीव्र प्रसार, कोरल विरंजन, समुद्र जल के तल में वृद्धि से शीथ भागों का डूबना, जलेशिथियों के

पिछलने से जल स्रोतों में कमी और उनके परिणामस्वरूप जलमय की समस्या इत्यादि। विकसित देशों से पास उन्नत प्रौद्योगिकी के मौजूद होने के कारण वे इन प्रभावों का आसानी से सामना कर लेते हैं परन्तु विकासशील देशों में गरीबी की मौजूदगी के कारण ये समस्याएं और अधिक व्यापक रूप धारण कर लेती हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए समय-समय पर ~~विपत्तियों~~ अनेक प्रयास किए जाये हैं जिनमें वैश्विक स्तर पर प्रयासों में 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, 1987 की बर्लिन आयोग की रिपोर्ट, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, 1994 का क्योटो प्रोटोकॉल, 2002 का जोहानसबर्ग का सतत विकास सम्मेलन, 2015 का पेरिस सम्मेलन इत्यादि प्रमुख हैं। इन सभी सम्मेलनों में विकासशील देशों द्वारा सहमत होकर

कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देश ज्यादा जिम्मेदार हैं अतः उन्हें इनके प्रभावों से निपटने के लिए विकासशील देशों की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता करनी चाहिए। इन सम्मेलनों में 'कॉमन बट डिफ्रेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CBDR)' के सिद्धान्त को मान्यता दी गई। 2010 में एक हरित जलवायु निधि का निर्माण किया गया, जिसमें प्रतिवर्ष विकसित देशों द्वारा 100 अरब डॉलर का योगदान दिया जाना है, परन्तु, इसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

इसके अलावा 'वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)' भी इस संबन्ध में एक वित्तीय तंत्र है। इसी के साथ वर्तमान समय में ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, हरित अर्थव्यवस्था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (CDM), कार्बन व्यापार इत्यादि अवधारणाओं को भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC)

के तहत 8 प्रमुख मिशनों का कार्यान्वयन, गरीबों की स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाने के लिए उज्ज्वला योजना, इलेक्ट्रिक रूब हाइड्रिड वाहनों को बढ़ावा देना, सौर गठबंधन की स्थापना में नेतृत्व की भूमिका, अपने ~~सबसे~~ ~~विशेष~~ 'INDC (Intended Nationally determined contribution)' की दायित्व, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को 2022 तक 175 गीगावाट करना इत्यादि शामिल हैं।

परन्तु अपर्याप्त प्रयासों के क्रियान्वयन के बावजूद भी जलवायु परिवर्तन की समस्या विकराल रूप धारण करते जा रही है। 'ग्लोबल इमिशन गैप रिपोर्ट' के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन दर में तो कमी आयी है परन्तु इनकी सकल मात्रा में अभी भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन प्रयासों की विफलता के पीछे अनेक कारक जिम्मेदार हैं जिनमें

विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के सहयोग का निम्न स्तर, अमेरिका जैसे देश के प्रेरित जलवायु समझौते से बाहर निकलने के कारण जलवायु परिवर्तन नियंत्रण कियान्तापों के क्रियान्वयन पर ठेस पहुँचना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तकनीक का भँगा होना तथा विकासशील देशों तक इसकी सीमित पहुँच का होना, नागरिकों में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता का निम्न स्तर, प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

वर्तमान में चीन तथा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व के सर्वाधिक हरित गृह गैसों के उत्सर्जक देश हैं। भारत में अभी भी लगभग २१% जनसंख्या विकट गरीबी का सामना कर रही है। इसलिए ~~अनेक~~ अनेक विकासशील देशों के समक्ष विकास आवश्यकताओं एवं जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण दोनों के बीच संतुलन प्राप्त करना अत्यावश्यक है।

इसके लिए वैश्विक समुदाय ही अपनी शीघ्र जिम्मेदारी की समझौते हुए तथा भावी पीढ़ी

के हितों की रक्षा के लिए मिलकर सशक्त प्रयास करने होंगे। ~~विकासशील~~ विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने हुए विकासशील देशों से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवानी होगी जिससे ये देश गरीबी एवं जलवायु परिवर्तन के दुष्चक्र से निकलकर अपने नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित कर सकें।

भारत से सभी विकासशील देशों के साथ एकजुट होकर नेतृत्वकर्ता के दायित्व का पालन करते हुए वैश्विक मंचों पर विकसित देशों पर दबाव बनाकर वित्तीय एवं प्रौद्योगिकीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

गरीबी व जलवायु परिवर्तन से निपटना विकासशील देशों के लिए एक असंभव कार्य है क्योंकि उनके पास वित्त एवं तकनीक का अत्यंत अभाव है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था को सहयोग सुनिश्चित करने का तत्काल प्रयास करना चाहिए ताकि व्यापक वैश्विक कल्याण को सुनिश्चित करके

समस्त विकास लक्ष्यों (SDG) को पूर्ति की जा सके। इसमें इन सर्वाधिक सुभेद्य नागरिकों की जलवायु परिवर्तन से निपटने की शक्ति में भी गृही होगी तथा वे विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना सर्वांगीण कल्याण सुनिश्चित करने में सफल हो पायेंगे।

अतः गरीबी व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोगी तथा समन्वयित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसे वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा का पालन करना समय की मांग प्रतीत होती है।

